भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 454

गुरूवार, 25 जुलाई, 2024/3 श्रावण, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा

454 श्री ईरण्ण कडाडी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों में से ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा और उन परियोजनाओं की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने में मौजूदा योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए कोई मानदंड विकसित किया है या कोई आकलन करवाया है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ रोजगार पैदा करने और देश की प्राचीन विरासत को प्रदर्शित करने हेतु ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को समवर्ती सूची में शामिल करने की योजना बना रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन (एसडी)' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके पर्यटन अवसंरचना विकास के उनके प्रयासों में सहायता करता है। पर्यटन मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिपथ थीम के तहत 2 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

राज्य/स्वीकृति वर्ष	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)**
बिहार / 2017-18	भितिहरवातुकौलिया का विकास-चंद्रहिया-	44.27
केरल / 2018-19	मालानाड मालाबार क्रूज पर्यटन परियोजना का विकास	57.35

अब मंत्रालय ने देश में स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) का नया रूप दिया है और इस योजना के अंतर्गत विकास हेतु 57 गंतव्यों का चयन किया है। यद्यपि चयनित स्थलों के सीमांकित क्षेत्र में ग्रामीण इलाके भी शामिल हैं तथापि मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 में 32.20 करोड़ रु. की राशि से उत्तराखंड में 'गुंजी में ग्रामीण पर्यटन क्लस्टर अनुभव' सहित 29 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना की चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी) नामक उप-योजना के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं और विकास हेतु योजना दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर वाइब्रेंट विलेज श्रेणी में निम्नलिखित 5 गंतव्यों सहित देश में 42 गंतव्यों को चिह्नित किया है:-

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	**गंतव्य**
अरुणाचल प्रदेश	किबिथो
हिमाचल प्रदेश	रक्छम, छितकुल
सिक्किम	नाथांग गांव
उत्तराखंड	माना गांव
उत्तराखंड	जाडुंग

समवर्ती सूची में पर्यटन को शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। तथापि पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 8 दिसम्बर, 2021 को भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति और रोडमैप तथा दिनांक 5 मई, 2022 को ग्रामीण होमस्टे के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति जारी की है। यह कार्यनीति ग्रामीण पर्यटन और ग्रामीण होमस्टे के विकास हेतु चिह्नित प्रमुख कार्यनीतिक स्तम्भों पर आधारित है। यह प्रमुख कार्यनीतिक स्तम्भ इस प्रकार हैं:-

1. ग्रामीण पर्यटन हेतु मॉडल नीतियाँ और उत्कृष्ट कार्यपद्धतियाँ
2. ग्रामीण पर्यटन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ और प्लेटफॉर्म
3. ग्रामीण पर्यटन हेतु क्लस्टरों का विकास
4. ग्रामीण पर्यटन हेतु मार्केटिंग सहायता
5. हितधारकों का क्षमता निर्माण
6. शासन एवं संस्थागत कार्यढॉचा

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार का अधीनस्थ स्वायत्तशासी निकाय भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान देश में ग्रामीण पर्यटन और ग्रामीण होमस्टे के संवर्धन तथा विकास हेतु योजनाओं तथा स्कीमों के समन्वयन और कार्यान्वयन में पर्यटन मंत्रालय की सहायता के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसी है।

भारत में ग्रामीण पर्यटन की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए ग्रामीण पर्यटन विलेज पोर्टल (www.rural.tourism.gov.in) तैयार किया गया है। इस वेबसाइट में भारत के ग्रामीण पर्यटन गंतव्यों, भारत में ग्रामीण होमस्टे आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध है।

पर्यटन मंत्रालय ने ऐसे गांव को सम्मानित करने के लिए उत्कृष्ट पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता की शुरूआत की है जो सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक सम्पदाओं के साथ एक पर्यटक गंतव्य का सर्वोत्तम उदाहरण हो, जो समुदाय आधारित मूल्यों, वस्तुओं और जीवनशैली का संरक्षण तथा संवर्धन करता हो और पर्यटन को सकारात्मक बदलाव, विकास तथा सामुदायिक कल्याण के साधनों में से एक बनाने के व्यापक लक्ष्य के साथ स्थायित्व को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणिक सभी रूपों में स्थापित करने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध हो।

पर्यटन मंत्रालय ने उत्कृष्ट ग्रामीण होमस्टे प्रतियोगिता की शुरूआत की जो ग्रामीण होमस्टे को अपनी अनोखी पेशकशों को दर्शाने के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जिससे पर्यटकों को नए और आकर्षक आवास विकल्प तलाशने का मौका मिलेगा।

पर्यटन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) की उत्कृष्ट पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में भाग लेता है। यह भारत के लिए वैश्विक परिदृश्य में स्थायित्व, संरक्षण और ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में की गई अपनी पहलों के प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। वर्ष 2021 में तेलंगाना के पोचमपल्ली को उत्कृष्ट पर्यटन गाँव के रूप में मान्यता मिली थी। वर्ष 2022 में खोनोमा को यूएनडब्ल्यूटीओ के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया था। वर्ष 2023 में गुजरात के कच्छ के धोरडो गाँव को उत्कृष्ट पर्यटन गाँव के रूप में चुना गया था और मध्य प्रदेश के मडला गाँव को उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया था।

सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में ग्रामीण पर्यटन के विकास हेतु एक कार्यबल का गठन भी किया गया है जिसमें केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों तथा उद्योग हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

****